



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 118]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1997/फाल्गुन 28, 1918

No. 118]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997

सा. का. नि. 161(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुमूली में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुमूली

नव मंगलूर पत्तन न्यास

कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) विनियम 1997 :

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का मण्डल निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम.—(i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) विनियम, 1997 कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित केन्द्र सरकार के अनुमोदन की तारीख से प्रदत्त होंगे।
2. पात्रता.—ये विनियम इन पर लागू होंगे।—(i) सेवांत अवकाश और निवृत्ति के पूर्व तैयारी के अवकाश तथा पुनर्नियुक्त सहित पत्तन के कर्मचारी सूची में आने वाले सभी कर्मचारी।
- (ii) परिवीक्षा अवधि में रहे व्यक्ति।
- (iii) प्रशिक्षु जो पत्तन न्यास में पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त है।
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार, अन्य बड़े पत्तन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पत्तन में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी बशर्ते उनकी प्रतिनियुक्ति शर्तों का प्राप्तधान हो।
- (v) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी गण।
- (vi) सूचीबद्ध माल संचालन श्रमिक जो नव मंगलूर पत्तन न्यास के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।
- (vii) जैसा की विनियम 3 में परिभायित है, धारा vii में सूचित मण्डल के कर्मचारी के परिवार सदस्य।

- (viii) पत्तन न्यास से निवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, चिकित्सा सुविधाएं समय-समय पर संशोधित “नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी” (निष्ठुति पश्चात् आहय और अंतरंग अंशदायी चिकित्सा हितलाभ) विनियम, 1991 के अनुसार पत्तन न्यास से प्रदान की जाएंगी ।
3. परिभाषा.—इस विनियमावली में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—(1) अधिनियम का अर्थ है महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ।
- (ii) “अनुमोदित अस्पताल” का अर्थ है, इन विनियमों के परिशिष्ट II में सूचित अस्पताल और अन्य कोई अस्पताल तथा नर्सिंग होम जो इस परिशिष्ट में शामिल करने के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है ।
- (iii) मंडल का अर्थ है, समय-समय पर संशोधित महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन गठित नव मंगलूर पत्तन के न्यासी गण हैं ।
- (iv) “अध्यक्ष” “उपाध्यक्ष” और “विभागाध्यक्षों” के अर्थ वही रहेंगे जो महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में ऋग्मण्डल गण हैं ।
- (v) “मुख्य चिकित्सा अधिकारी” का अर्थ पत्तन न्यास अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा विभाग के प्रधान हैं ।
- (vi) कर्मचारी का अर्थ है, पत्तन न्यास के अस्थायी व स्थायी कर्मचारी । [इन विनियमों के विनियम 2 के उप विनियम (i) से (iv) तक देखें] ।
- (vii) “परिवार” का अर्थ है पति या पत्नी जैसी स्थिति हो महिला कर्मचारी का विकल्प के विषय में सास-ससुर, अविवाहिता अहनें, विधवा अहनें, विधवा पुत्रियां, नाबालिंग भाई तथा कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित किसी कर्मचारी के ददक पुत्रों सहित न्याय संगत बच्चे । (पत्नी या पति के लिए आश्रित लागू नहीं) ।

- टिप्पणी 1 : परिवार के किसी सदस्य को कर्मचारी पर आश्रित तभी माना जाएगा जबकि पेंशन और उपदान के समान पेंशन सहित सभी ओरों से उनकी आय कुल मिलाकर रु. 500 से अधिक नहीं रहता हो ।
- टिप्पणी 2 : जहां पति और पत्नी दोनों पत्तन के कर्मचारी हैं, उन्हें और उन पर आश्रितों के सहित, इन दोनों में से किसी एक श्रेणी अनुसार चिकित्सा रियायत प्रदान किया जा सकता है । इसके लिए, उनको अपने-अपने विभाग के प्रधानों को एक संयुक्त घोषण पत्र देना होगा कि पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के चिकित्सा

परिचर्या और उपचार से संबंधित लगने वाले चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए कौन आवेदन करेगा । उपर्युक्त घोषणा द्वि-प्रति में प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित विभागों द्वारा उनके अपनी-अपनी सेवा बहियों के व्यक्तिगत फाइलों में लगा देना चाहिए । यह घोषणा इन दोनों में से किसी एक द्वारा अपनी पदोन्ति, अंतरंग, त्यागपत्र आदि के अवसर पर दिए जाने वाले संयुक्त लिखित मांग को रखने तक जारी रहे गा । वैसे संयुक्त घोषणा पत्र के अभाव में, चिकित्सा रियायत पत्नी के द्वारा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पति की श्रेणी के अनुसार होना चाहिए ।

टिप्पणी 3 : यदि कर्मचारी के पति या पत्नी, जो भी स्थिति हो, जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अन्य पत्तन न्यास/निधि संगठन जो चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं, वे या तो इन विनियम के अधीन या वह संगठन जिसमें वह काम कर रहा/रही है, इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं । चुनने अथवा संशोधित करने की अवधि ऊपर नोट 2 के अनुसार होगा ।

टिप्पणी 4 : प्रत्येक कर्मचारी को अपने अपने विभागाध्यक्ष से व्यक्तिगत चिकित्सा पहचान पत्र और परिवार चिकित्सा पहचान पत्र जो पत्तन न्यास अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, लेना होगा जिसमें अपने परिवार के सदस्यों का एक-एक फोटो लगा रखा जाना चाहिए । चिकित्सा के लिए दाखिल होते समय व्यक्तिगत चिकित्सा पहचान पत्र/परिवार चिकित्सा पहचान पत्र को पेश करने में विफल होने पर इस उपचार को लेने के लिए कर्मचारी/सदस्य उनके परिवार के लिए पत्तन न्यास अस्पताल/चिकित्सालय जो इस विनियम के अधीन आते हैं, अर्ह नहीं माने जाएंगे ।

नोट : पत्तन के महिला कर्मचारियों के सास-ससुर की इस हितलाभ का विस्तरण अर्थात् जब पत्तन न्यास के कर्मचारी/पत्तन न्यासेतर कर्मचारी से व्याह किया जाता है तो यह विकल्प होना चाहिए कि अपने माता-पिता को देय है या कि सास-ससुर को ।

(viii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का अर्थ है, पत्तन न्यास के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग का प्रधान है ।

(ix) “चिकित्सा अधिकारी” का अर्थ है, नव मंगलूर पत्तन न्यास के चिकित्सा अधिकारी, निवासी-व-वरिष्ठ चिकित्सा

- अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अंशकालिक अधिकारी के लिए पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ एवं अनुमोदित अस्पताल/राज्य सरकार के अस्पतालों में रोगियों की देख-रेख करने वाले चिकित्सा अधिकारी ।
- (x) “चिकित्सा परिचर्या” का मतलब है अस्पताल, पत्तन न्यास अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल अथवा राज्य सरकार के अस्पताल, रोग विशेषज्ञ के लिए पेशौलाजी, बैकटीरियॉलाजी, रेडियॉलाजी, कार्डियॉलाजी संबंधी अथवा अन्य तरह की परीक्षा के लिए कर्मचारी का निवास सहित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिस विशेषज्ञ का परामर्श जरूरी है वह परिचर्या ।
- (xi) “रोगी” का मतलब है पत्तन न्यास का कर्मचारी, उसके परिवार के पात्र मदम्य और विनियम 2 के अधीन आने वाले वे लोग जो बीमार पड़े हों और पत्तन अस्पताल/अनुमोदित अस्पतालों में चिकित्सा ले रहे हों ।
- (xii) “निजी डाक्टर” या “निजी अस्पताल” का अर्थ है, ऊपर बताए गए उप विनियम (2) में सूचित पत्तन के डाक्टर, अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल के अलावा एक पंजीकृत चिकित्सक या अस्पताल ।
- (xiii) मंजूरी प्राधिकारी का अर्थ है, इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित अस्पताल प्रभारों के प्रतिपूर्ति के मंजूरी प्राधिकारी ।
- (xiv) “पत्तन का अस्पताल” का अर्थ है, नव मंगलूर पत्तन न्यास का मुख्य अस्पताल और मुख्य अस्पताल से संबद्ध चिकित्सालय जो अलग-अलग जगह में कार्य कर रहे हैं ।
- (xv) “चिकित्सा” का अर्थ है, सभी वैद्यकीय एवं शास्त्र चिकित्सकीय सुविधाएं जो पत्तन न्यास अस्पताल एवं समय-समय पर पत्तन द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पताल में उपलब्ध नीचे दर्शित हैं जिसमें ये शामिल हैं :—
- (क) पेशौलाजी, बैकटीरियॉलाजी, रेडियॉलाजी और अन्य तरह के प्रयोग जिसे पत्तन का चिकित्साधिकारी आवश्यक समझता है ।
- (ख) वे औपध, टीका, सीरम और अन्य चिकित्सकीय साधन जिसे पत्तन के चिकित्सा अधिकारी आवश्यक समझते हैं, जो साधारणतः पत्तन के अस्पताल में उपलब्ध नहीं होते और जिसे रोगी की स्थिति को देखते हुए उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए या और भी गंभीर बनने से रोकने के लिए आवश्यक मानकर चिकित्साधिकारी प्रमाणित करते हों, जिनमें ये शामिल नहीं होंगे :—
- (i) ये उत्पादन जो औपध न होकर केवल आहार, टॉनिक, शौच आवश्यकताएं, अथवा रोगाणु नाशक हैं तो केन्द्र सरकारी चिकित्सा परिचर्या नियम की अनुसूची-I में उल्लिखित हैं ।
- (ii) केन्द्र सरकारी चिकित्सा परिचर्या नियम के अनुसूची-II में उल्लिखित महंगे औपध, टॉनिक, विरेचक और अन्य टिकिया तथा स्वास्थ्य तैयारियां और वे औपध जिनके समतुल्य चिकित्सकीय दवाई उपलब्ध हैं ।
- (iii) केन्द्र सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियम के परिशिष्ट में दी गई औपध सूची और वे सामग्री जिन्हें भारतीय और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए मुचित किया जा सकता है ।
- (ग) यह मुश्रूपा मेवा पत्तन न्यास अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है ।
- (घ) केन्द्र सरकारी चिकित्सा परिचर्या नियम 1944 में सूचीबद्ध कृत्रिम अंग/कृत्रिम सहायक साधन की आपूर्ति और पत्तन न्यास के चिकित्साधिकारियों के सिफारिश पर उनको बदलता ।
- (ङ) रक्त आधान ।
- (च) पत्तन न्यास अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के सिफारिश पर बनाई गई दंतावली और कृत्रिम अंग व अंग ।
- (छ) वह आवास जो साधारणतः अस्पताल में दिया जाता है या उसकी श्रेणी के अनुसार मात्र है । जहां तक अनुमोदित अस्पतालों में लागू करने योग्य श्रेणी की बात है, कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मणिपाल को प्रतिपूर्ति के लिए मानदंड माना जाएगा । जहां आहार का प्रावधान सहित आवास के दर में 20 प्रतिशत घटाया जाना चाहिए ।
- नोट:** जब संबंधित कर्मचारी को उसकी श्रेणी के अनुसार का आवास उपलब्ध नहीं रहता है तो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रमाण पत्र रहने पर उच्चतर श्रेणी का आवास उसे दिया जा सकता है ।
- (i) जहां रोगी के दाखिल के समय उसकी श्रेणी के अनुकूल आवास उपलब्ध नहीं रहा हो ।
- (ii) जहां उचित श्रेणी का आवास मिलने तक अस्पताल में रोगी को दाखिल न करना उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरा हो ।

(ज) इस विनियम के उपनियम के (x) विवरणानुसार वैसे विशेषज्ञों का परामर्श जिसमें आहार अथवा ऊपर उप विनियम (ज) के उल्लेखानुसार कर्मचारी की मांग पर दिए उच्चतर आवास के प्रावधान को छोड़कर ।

4. चिकित्सा परिचर्या।—(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुफ्त में चिकित्सा परिचर्या लेने का रोगी पात्र होगा ।

(ii) जब उप विनियम (1) के अधीन रोगी मुफ्त में चिकित्सा परिचर्या पाने के लिए पात्र रहता है, तो वैसी कोई चिकित्सा परिचर्या के लिए उसके द्वारा दी गई राशि का उस चिकित्सा अधिकारी के लिखित रूप में प्रमाणपत्र पेश करने पर पत्तन न्यास द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए ।

(iii) चिकित्सा परिचर्या, चिकित्सा उपचार से भिन्न है और ऐसे संदर्भ में पुनर परामर्शों की जरूरत नहीं है । पत्तन न्यास अस्पताल, जहां परामर्श मुफ्त होता है, के चिकित्सा अधिकारी को छोड़कर अलोपतीय पद्धति में चिकित्सा अधिकारी के कमरे में या रोगी के घर में दस दिन में गरिष्ठतम चार परामर्श और भारतीय या होमियोपैथिय पद्धति के लिए 20 दिन स्थीकार्य है । यदि 10/20 दिन से भी ज्यादा दिन के लिए उपचार की जरूरत नहीं है और अस्पताल में दाखिल करना भी जरूरी नहीं है । लेकिन 4 परामर्श से भी ज्यादा आवश्यक है तो वैसे मामलों को अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग को पेश करना चाहिए । इससे भी विपरीत स्थिति हो तो रोगी को पत्तन न्यास अस्पताल या अनुमोदित अस्पतालों में से एक में उपचार के लिए भेजना चाहिए । पत्तन न्यास के अस्पताल को छोड़कर अन्य अस्पतालों में पहले और बाद के परामर्श तथा इंजक्शनों के दर को केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को देने के लिए समय-समय पर निर्धारित दर के आधार पर प्रतिपूर्ति किया जाएगा ।

5. चिकित्सा परिचर्या यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता।—(i) जब रोगी के बीमार पड़ने की जगह चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष के कर्निष्टतम रास्ते में 8 कि. मी. से भी दूर पड़ता है :—

(क) रोगी परामर्श कक्ष तक जाने और आने के लिए यात्रा भत्ता के लिए,

(ख) यदि रोगी यात्रा करने के स्थिति में भी नहीं रहता है तो रोगी के बीमार रहने की जगह तक आने और जाने के लिए चिकित्साधिकारी यात्रा भत्ता लेने के लिए पात्र बनता है ।

(ii) दावे ऊपर विनियम (1) के अनुसार है तो चिकित्साधिकारी का यह प्रमाणपत्र साथ में रहना चाहिए कि वह चिकित्सा परिचर्या आवश्यक था और यदि आवेदन इस उप-विनियम

(ख) के अधीन है तो यह प्रमाणपत्र रहना चाहिए कि रोगी यात्रा करने की स्थिति में भी नहीं था ।

(iii) निम्नलिखित संदर्भों में यात्रा भत्ता की स्थीकार्यता इस प्रकार होगी :—

(क) कर्मचारियों के लिए (दैनिक भत्ता रहित) वास्तविक खर्च यात्रा दर पर मैलेज भत्ता तक सीमित और परिषार के मदम्बो के लिए (दैनिक भत्ता रहित) वास्तविक यात्रा प्रभार यात्रा दर पर मैलेज भत्ते के आधे के लिए सीमित ।

(ख) अम्बुलेंस प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए पत्तन न्यास अंबुलेंस के संदर्भ में अंबुलेंस को भाड़े पर लेने हेतु बनाये गये विनियम के आधार पर देखा जाएगा । पत्तन न्यास अस्पताल अंबुलेंस के अलावा अन्य अंबुलेंस लेने के संदर्भ में प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तानुसार होगी :—

(i) पत्तन न्यास अस्पताल के चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र हो कि पत्तन न्यास अस्पताल का अंबुलेंस उपलब्ध नहीं है ।

(ii) चिकित्साधिकारी का लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र हो कि रोगी की यात्रा अन्य किसी प्रकार का यात्रा माध्यम द्वारा करने से रोगी की जान निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी अथवा पूरी तरह से उसकी स्वास्थ्य स्थिति को बिगड़ा देगी ।

(iii) चिकित्साधिकारी को अपने प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि क्या रोगी को उपचार देने की जगह ले जाने के लिए या कुछ खास डाक्टरी जांच के उद्देश्य से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को ले जाने के लिए अंबुलेंस का उपयोग किया गया था ।

(ग) इन आदेशों के अधीन स्थीकार्य दरों पर एक परिचारक/रक्षक यात्रा भत्ता लेने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि चिकित्साधिकारी द्वारा ये प्रमाणपत्र हो कि परिचारक रहत रोगी कि यात्रा सुरक्षित नहीं है और कि उपचार देने के जगह तक एक परिचारक/रक्षक का साथ रहना आवश्यक है ।

6. पत्तन न्यास अस्पताल/चिकित्सालयों में रोगी मुफ्त उपचार/परिचर्या के लिए पात्र है ।

7. चिकित्सोपचार।—(i) पत्तन न्यास अस्पताल में रोगी मुफ्त में उपचार/अंतरंग रोगी के रूप में उपचार पाने वाला पात्र बन जाता है ।

(ii) जहां चिकित्साधिकारी रोगी को उपचार के लिए अनुमोदित अस्पताल या राज्य सरकार के अस्पताल को भेजता है, वाहे पत्तन न्यास के अस्पताल में सुविधाओं की कमियों के कारण हो या बीमार पड़ने वाले रोगी का घर पत्तन न्यास अस्पताल से 8 कि. मी. से दूरी पर रहने के कारण हो, तो इस संबंध में

मुख्य चिकित्सा 'अधिकारी' की विशेष अनुमति ली जानी चाहिए। यदि उपचार लेने के पहले ऐसी अनुमति ली नहीं जा सकती है। उपचार के लिए उसे दर्खिल करने के बाद भी सही उसके कारण बताते हुए तुरंत उसकी अनुमति ली जानी चाहिए।

- (iii) ऊपर उप-विनियम (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वैसे उपचार के लिए कर्मचारी द्वारा कोई राशि दी गई हो तो इस संबंध में चिकित्साधिकारी का एक लिखित प्रमाण पत्र के पेश करने पर पत्तन द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। विनियम 3 के उपविनियम (xv) के अंतर्गत आने वाले आवास सहित विभिन्न सेवा प्रभारों के प्रतिपूर्ति के लिए कस्टरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मणिपाल या मरकारी अस्पताल के दर (जो भी अधिक हो) वरिष्ठतम् सीमा मानी जाएगी।

8. निवास में उपचार.—(i) यदि चिकित्साधिकारी का यह अभिप्राय है कि एक उचित अस्पताल के अभाव में या उसके दूर में रहने के कारण अथवा बीमारी की गंभीरता के कारण रोगी को ऊपर विनियम 7 में बताने के अनुसार उपचार नहीं दी जा सकती तो रोगी अपने निवास में ही उपचार पा सकता है।

- (ii) ऊपर के उप-विनियम (i) के अनुसार उपचार पाने वाले रोगी, अपने उपचार के लिए, लगने वाले खर्च, जो इस विनियम के अधीन उसका अपने घर में उपचार पाने के लिए जितना खर्च लगता हो उसी राशि के बराबर की राशि, पाने के लिए हकदार होगा।
- (iii) ऊपर के उप-विनियम (ii) के आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निम्न उल्लेख सहित प्रमाणपत्र के साथ होने चाहिए।
- (क) ऊपर (i) के संबंध में उसके अभिप्राय के कारण।
- (ख) ऊपर के उप-विनियम (ii) के अनुसार वैसी ही उपचार के खर्च।

9. अन्य चिकित्सा सुविधाएं.—इन विनियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की प्रतिपूर्तियां भी स्वीकार्य हैं।

- (i) “योन रोग संबंधी” बीमारियां और “सन्निपात”।
- (ii) परिवार सुरक्षा उपाय के अनुसार बंधीकरण उपचार।
- (iii) यदि केन्द्र मरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों/संस्थाओं द्वारा वैद्यकीय गर्भ समाप्ति करने पर।

- (iv) दृष्टिपोषकार जैसे दंतकर्पण, स्फेलिंग व ममौड़ों का उपचार, दांत भरना, रूट केनाल उपचार व दांत संबंधी बड़े किस्म के उपचार जैसे हंवन्मिथ रोग, कर्मचार यदि मानसिक अस्वस्थता या अन्य प्रकार की अशक्ततायुक्त हैं और उसका मूल कारण दांतों का दोष ही है तो पूरे दांतों को निकालना।
- (v) पंटी-खींची उपचार।
- (vi) अधखुली (स्किंट) आंख को ठीक करना।
- (vii) ई.एन.टी. विशेषज्ञ की सिफारिश पर श्रव्य साधन की खरीद/पुनःस्थापन/मरम्मत ममायोजन। अदायगी सीधे मुहूर्या करने वाले एजेन्सियों को ही की जाएगी अशर्ते कि वरिष्ठतम् सीमा केन्द्र मरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार हो।
- (viii) कर्मचारी की पत्नी पत्तन न्यास अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल/राज्य मरकार के अस्पतालों में चिकित्सा परिष्वर्या व प्रसवावस्था के उपचार लेने के पात्र रहेगी। इसमें प्रसवपूर्ति तथा प्रसव के बाद के उपचार भी शामिल हैं। यदि मरकार या स्थानीय संगठनों के शिशु-कल्याण व प्रसव केन्द्र के स्टाफ द्वारा अपने केन्द्र में निर्धारित दर पर किए गए प्रसव निवास के प्रमूर्ति प्रभार प्रतिपूर्ति होंगे।
- (ix) भारतीय और होमियोपैथी पद्धति के औषधीय उपचार के लिए रोगी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर पर प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य होंगे।
10. अस्पताल प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राप्त आवेदनों की मंजूरी क्रमशः — (i) इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति के दावे को कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (फिलहाल केन्द्र मरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र और आवश्यकता प्रमाण पत्रों को ही पत्तन न्यास के कर्मचारियों को भी निर्धारित किया गया है) में उपचार पूरे होने के दिन से 90 दिन के अंदर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उपचार को और भी बढ़ावा जा रहा है और चल रहा है तो आवेदनों को 30 दिनों से कम न होने वाली अवधि में बार-बार प्रस्तुत करते रहना चाहिए।
- (ii) निर्धारित ममय सीमा के बाहर की अवधि में प्रस्तुत दावों को प्रत्येक की अर्हता के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष माफ कर सकते हैं। कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने के साथ-साथ अस्पतालों से, जहाँ रोगी का उपचार हुआ था, निम्नलिखित बातचर और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) रोगी का पूरा नाम महिल अस्पताल का बिल और यदि परिवार का सदस्य है तो उसका नाम और मर्मांधि कर्मचारी का पूरा विवरण। विभिन्न प्रभारों का विवरण भी रहना चाहिए।

- (ख) यदि बिल अपने आप एक रसीद नहीं है तो भुगतान करने के संबंध में एक रसीद ।
- (ग) दाखिल और मुक्त करने के संबंध में प्रमाण पत्र ।
- (घ) औपधों की खरीद के नकद बिल (उस पर मुहर या विक्रेता की प्राप्ति सूचना की जरूरत नहीं है) जिस पर रोगी की देखरेख करने वाले अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
- (ङ) पत्तन न्यास अस्पताल के चिकित्साधिकारी, जिसने अनुमोदित अस्पताल के लिए भेजा था, द्वारा अनुमोदित अस्पताल जाने के लिए दिया गया प्रमाण पत्र ।
- (ii) कर्मचारियों के आवेदनों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा जांच करके जहां आवश्यक हो अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर प्रति-हस्ताक्षर करने के बाद वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को उसकी अदायगी के लिए अप्रेपित करना चाहिए । पत्तन न्यास/अनुमोदित/राज्य सरकार के अस्पतालों में परिचर्या/उपचार लेने से संबंधित आवेदनों के अलावा प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त 'आवेदन जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन और अथवा अध्यक्ष की मंजूरी की जरूरत है तो उन दावों को इन विनियमों के अधीन छूट देकर अध्यक्ष द्वारा मंजूरी देने के पहले वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए ।
- (iv) हर विभाग में लगातार दी जाने वाली प्रतिपूर्तियों का क्रमगत लेखा-जोखा रखने के लिए एक उपराजिस्टर खोलना चाहिए जिससे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधाओं का दुरुपयोग रोकने हेतु आवधिक समीक्षा की जा सके ।
- (v) एलोपेथी पद्धति का उपचार प्राप्त एक रोगी औपध व कॉम्मेटिक अधिनियम व नियम के अधीन अनुज्ञाप्ती प्राप्त सभी औपध भंडारों से औपध खरीद सकता है । आयुर्वेदी यूनानी मिद्र व होमियोपैथी ढंग से उपचार प्राप्त रोगी मात्र उन्हीं अधिकृत विक्रेताओं से दवाई खरीद सकता है जिनकी सूची केन्द्रीय मेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1944 में दी गई है ।

11. अनुमोदित अस्पतालों को भुगतान करने की विधि.— विनियम 3(ii) के अधीन पत्तन द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में उपचार के लिए भेजे गए सभी कर्मचारियों के सभी मामलों में कर्मचारी द्वारा देय प्रभारों को पत्तन न्यास द्वारा उन अस्पतालों को सीधे भुगतान किया जाएगा । अंतिम आवेदन प्राप्त होने के बाद यदि यह पाया जाता है कि अदा की गयी राशि स्वीकार्य राशि से अधिक है तो अधिक्षय राशि का कर्मचारी को दिए जाने वाले भेतन से तत्काल मासिक किस्तों में, चार किस्तों से अधिक न होते हुए, बमूल किया जाएगा । मामलों की अर्हता के परीक्षण करके अध्यक्ष किस्तों की मंख्या बढ़ा सकते हैं ।

12. व्याख्या.— इन विनियमों की व्याख्या में अगर कोई संदेह उठता है तो मंडल द्वारा उसका समाधान किया जाना चाहिए ।

13. छूट देने का अधिकार.— इन विनियमों की किसी शर्तों पर छूट देने का अधिकार मंडल पर निर्भर रहना चाहिए ।

14. निरस्त व लागू होना.— इन विनियमों के प्रयुक्त होने पर उसके आरंभ होने के पहले प्रचलित प्रत्येक नियम, विनियम, संकल्प या आदेश के लिए, जहां तक इन विनियमों में प्रावधान बनाए गए हैं, लागू होंगे ।

परिशिष्ट-।

अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए मंजूरी प्राधिकारी :

(विनियम 3)

1. विभागाध्यक्षों से संबंधित अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए }
2. विनियम 10(iii) के अनुसार छूट
3. विभागाध्यक्षों के प्रधानों के अतिरिक्त श्रेणी 1 से 4 के कर्मचारी }
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

परिशिष्ट-॥

अनुमोदित अस्पताल

[विनियम 3(ii)]

1. फादर मुल्लर्स अस्पताल, कंकनाडि, मंगलूर (1983-84 की बैठक सं. 3 की मद सं. 8)
2. कन्तूरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मणिपाल समूह अस्पताल के दक्षिण कन्ड जिले में स्थित विस्तरण/शाखाएं ।
(1986-87 की बैठक सं. 9 की मद 15)
3. डा. तेन्से माधव अनंत पै रोटरी अस्पताल, मंगलूर (1989-90 की बैठक सं. 6 की मद 19)
4. यूनिटी हेल्थ कॉम्प्लेक्स, कंकनाडि, मंगलूर, सामान्य अस्पताल प्रभार से रिआयती दर 30 प्रतिशत छूट में ।
(1989-90 की बैठक सं. 6 की मद सं. 21)

5. संत मार्थास अस्पताल बैंगलूर—ट्रेड प्रमोशन सेंटर बैंगलूर में नव मंगलूर पत्तन न्यास के कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए। अस्पताल में, नव मंगलूर पत्तन न्यास द्वारा रु. 5000 की सुरक्षा जमाराशि रखी गयी है।
(1990-91 की 3 बोर्ड बैठक की मद सं. 10)

विनियम 7, 8, 9, 10, 11 :

के. से. चि. प. नियम से लिया गया है।

टिप्पणी :

के. से. चि. प. नियम और अन्य पत्तनों से प्राप्त विनियमों में पत्तन के लिए आवश्यक संशोधन करके और न भ प न्यास में प्रचलित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विनियम को बनाया गया है।

संदर्भ और नोट

विनियम 2 :

उप-विनियम (i) और (iv) मद्रास पत्तन न्यास विनियम से लिया गया है।

उप-विनियम (ii), (iii) के. से. चि. प. नियम से लिया गया है।

उप-विनियम (v), (vi) और (viii) मद्रास पत्तन न्यास तथा नव मंगलूर पत्तन न्यास से हैं।

उप-विनियम (vii) मुरगांव से लिया गया है।

विनियम 3 :

उप-विनियम (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) मद्रास पत्तन न्यास से लिया गया है।

उप-विनियम (vii) और (xv) मद्रास पत्तन न्यास तथा के. से. चि. प. नियम से हैं।

उप-विनियम (x) और (xii) मुरगांव से।

विनियम 4 :

मुरगांव तथा के. से. चि. प. नियम से।

विनियम 5 :

उप-विनियम (i) से (iii) के. से. चि. प. नियम।

उप-विनियम (iv) 1992-93 की बोर्ड बैठक की मद सं. 7
(30-1-1993)

विनियम 6 :

मद्रास, मुरगांव से लिया गया है।

- (ii) कस्तूरबा मेडिकल अस्पताल, मणिपाल जिसके लिए केन्द्र सरकार की मान्यता प्राप्त है, के. से. चि. प. नियमावली 2(घ) के अधीन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सोपचार के लिए और प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत है। (अस्पताल भी 10 प्रतिशत रियायत दे रहा है) पत्तन न्यास कर्मचारियों के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित अस्पतालों के लिए मद्रास पत्तन न्यास भी वे ही स्वीकार करता है। पत्तन न्यास कर्मचारियों के लिए मद्रास पत्तन न्यास भी वे ही स्वीकार करता है। पत्तन न्यास मंडल द्वारा चिकित्सा के लिए अनुमोदित अस्पतालों जो इन विनियमों में परिशिष्ट 11 में दिए गए विनियम की स्थिति के लिए मद्रास पत्तन न्यास से अनुमोदित अस्पताल क. मे. का. अस्पताल मणिपाल के लिए केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत श्रेणी ही मान्य है। इसलिए पहले ही सरकार द्वारा अनुमोदनानुसार पूरे अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है यशर्ते कि अधिकतम सीमा कॉलेज के दरानुसार ही।
- (iii) निवृत्त कर्मचारियों और अम्बुलेन्स को भाड़े पर लेने के बारे में अलग विनियम रखे गये हैं।
- (iv) एलोपैथिक पढ़ति के विषय में अस्थीकार्य तथा भारतीय व होमियोपैथि पढ़ति के लिए स्वीकार्य औषधों की सूची के. से. चि. प. नियम से ली गयी है।
- (v) आवेदन का प्रपत्र और अत्यावश्यकता का प्रमाण-पत्र के. से. चि. प. नियम से लिया गया है।
- (vi) उपचार के लिए अनुमोदित निजी अस्पतालों की सीधी अदायगी के प्रावधान को के. से. चि. प. नियम में उपलब्ध अस्पतालों को सीधे भुगतान करने के लिए प्रावधान से लिया गया है।

[फा. सं. पी. आर.-12016/26/95-पी.ई.-I]

के. वी. राव, मंयका सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1997

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees' (Medical Attendance) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

NEW MANGALORE PORT TRUST
EMPLOYEES' (MEDICAL ATTENDANCE)
REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes the following regulations.

1. Short Title

- (i) These regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees' (Medical Attendance) Regulations, 1997.
- (ii) They shall come into effect from the date on which the approval of the Central Government is published in the Official Gazette.

2. Eligibility

These regulations shall apply to :

- (i) All the employees borne on the Schedule of Employees of the Board including those employees on terminal leave and on leave preparatory to retirement and reemployed employees.
- (ii) A probationer.
- (iii) Apprentices who are in the whole time service of the Port Trust Board.
- (iv) All employees on deputation to the Port Trust Board from the State/Central Governments, other Port Trusts and Public Sector Undertakings subject to the provisions of their terms of deputation.

- (v) Central Industrial Security Force Personnel.
- (vi) Listed cargo handling workers under the direct administrative control of the New Mangalore Port Trust.
- (vii) The members of family of the employees of the Board listed at Clause vii as defined in Regulation 3.
- (viii) In the case of retired employees of Port Trust Board medical facilities from the Port Trust Board will be made available in accordance with the New Mangalore Port Trust employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefits after Retirement) Regulations, 1991 as amended from time to time.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires :—

- (i) 'Act' means the Major Port trust Act, 1963.
- (ii) 'Approved Hospital' means the Hospitals listed in Appendix-II of these Regulations and any other Hospitals and Nursing Homes as may be prescribed by the Board from time to time for inclusion in this Appendix.
- (iii) 'Board' means the Board of Trustees of the Port of New Mangalore as constituted under the Major Ports Trust Act, 1963 as amended from time to time.
- (iv) 'Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Heads of Department' shall have the meaning assigned to them respectively in the Major Port Trust Act, 1963.
- (v) 'Chief Medical Officer' means the Chief Medical Officer of the Port Trust Board and Head of the Medical Department.
- (vi) 'Employee' means temporary or permanent employee of the Port Trust Board [also see sub-regulations (i) to (iv) of Regulation 2 of these Regulations].
- (vii) 'Family' means the wife or husband as the case may be, parents or parents-in-law as per option in the case of female employees, unmarried sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers and legitimate children including adopted children of an employee wholly dependent on the employee (dependency not applicable for wife or husband) and will include unemployed daughters.

NOTE 1. The members of the family are treated as dependent only if their income from all sources including pension and pension equivalent of gratuity does not exceed Rs. 500/ p.m.

2. Where both the husband and wife are Port Trust employees, they as well as eligible dependents, may be allowed to avail of the medical concessions according to the status of either of these. For this purpose, they should furnish to the respective Heads of

Departments a joint declaration as to who will prefer the claim for reimbursement of medical expenses incurred on the medical attendance and treatment in respect of wife/husband and other members of the family. The above declaration should be submitted in duplicate and a copy of each shall be recorded in the personal file of each of them in their Service Records in the respective departments. This declaration shall remain in force till such time as it is revised on the express request in writing by both the husband and wife e.g. in the event of promotion, transfer, resignation etc. of either of the two. In the absence of such a joint declaration, the medical concession shall be availed of by the wife and other members of the family according to the status of husband.

3. The husband or wife of the employee, as the case may be, who is employed in a State Govt./Central Govt./Public Sector Undertaking/another Port Trust/ Private Organisation which provide medical services, would be entitled to choose either the facilities available under these Regulations or those provided by the Organisation in which he/she is employed. The procedure for making the choice or revision will be the same as at Note 2 above.
4. Every employee shall obtain from the head of his/her department, the personal medical identity card and the family medical identity card issued by the Trust's 'Chief Medical Officer' duly furnishing the particulars of his/her family members. The identity card should contain the photographs of all the members of the family included in the family identity card. Failure to produce the personal medical identity card /family medical identity card at the time of reporting for treatment will make the employee/members of his/her family concerned ineligible for treatment in the Trust's Hospital/dispensaries under these Regulations.

NOTE : Extension of benefits to Parents-in-laws of female Port Trust employees i.e. choice to include either Parents or Parents-in-law when married to a Port Trust employee/non-Port Trust employee.

- (viii) 'Financial Adviser and Chief Account Officer' means the Financial Adviser and Chief Account Officer of the Port Trust Board and head of the Finance Department.
- (ix) 'Medical Officer' means the doctor in employment in the Medical Department of the New Mangalore Port Trust Board including Medical Officer, Resident-cum-Senior Medical Officer, Chief Medical Officer and Specialists appointed by the Port Trust Board on part-time basis as well as Medical Officers in charge of the patients at the approved hospitals/State Govt. hospitals.

- (x) 'Medical Attendance' means attendance in hospital (port Trust hospital, approved hospitals or State Govt. Hospitals) or at the residence of the employees including such Pathological, Bacteriological, Radiological, Cardiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis and such consultation with a specialist as may be considered necessary by the Medical Officer.
- (xi) 'Patient' means the employee of the Port Trust Board, any of his/her eligible family members and any of those covered under Regulation 2 who has fallen ill and undergoing treatment/medical attendance in the Trust's Hospital/approved hospitals.
- (xii) 'Private Doctor' and 'Private Hospital' means a registered medical practitioner/hospital other than the Board's doctor/hospital/approved hospitals as per Sub-Regulation (ii) above.
- (xiii) "Sanctioning authority" means the sanctioning authority for the purpose of re-imbursement of hospital charges as prescribed in Appendix-I to these Regulations.
- (xiv) 'Trust's Hospital' means the New Mangalore Port Trust main hospital and dispensaries attached to the main hospital functioning at different places.
- (xv) 'Treatment' means the use of all medical and surgical facilities available in the Trust's Hospital as well as in the other hospitals as approved by the Board from time to time and includes :—
 - (a) the employment of such Pathological, Bacteriological, Radiological and other methods as are considered necessary by the Trust's Medical Officer;
 - (b) the supply of such medicines, vaccines, serum and other Therapeutic substances as may be prescribed by the Trust's Medical Officers as are not ordinarily available in the Trust's Hospital and which are certified by the Medical Officer in writing to be essential for the recovery or for the prevention of serious deterioration in the condition of the patient except :
 - (i) preparations which are not medicines but are primarily foods, tonics, toilet preparations or disinfectants as specified in Schedule I to the Central Government Medical Attendance Rules.
 - (ii) Expensive drugs, tonics, laxatives or other detergent and proprietary preparations as specified in Schedule II to the Central Government Medical Attendance rules and in respect of which drugs of equal therapeutic value are available.

- (iii) List of medicines and the items which can be prescribed in respect of Indian and Homoeopathic systems of Medicines is detailed in an Appendix to Central Government Servants Medical attendance Rules.
 - (c) Such Nursing as considered necessary by the Medical Officers of the Port Trust Hospital.
 - (d) Supply of Artificial limbs, corrective artificial appliances as listed out in Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and their replacement as recommended by the Medical Officers of the Port Trust Hospital.
 - (e) Blood transfusion.
 - (f) Supply of denture and artificial eye and limb as recommended by the Medical Officers of the Port Trust Hospital.
 - (g) such accommodation as is ordinarily provided in the Hospital and is suited to his status. In the case of approved Hospitals the status as applicable in the case of Kasturba Medical College, Hospital, Manipal will be the criteria for regulating the reimbursement. Where the rates for accommodation include provision of diet, the rate shall be reduced by 20%.
- NOTE :** In the event of accommodation suited to the status of the employee concerned being not available accommodation of a higher class may be allotted provided it can be certified by the Medical Superintendent of the Hospital.
- (i) that accommodation of the appropriate class was not available at the time of admission of the patient and
 - (ii) that the admission of the patient into the Hospital could not be delayed without danger of his/her health until accommodation of the appropriate class becomes available.
 - (h) such specialist consultation as described in Sub-Regulation (x) of this regulation but does not include diet or provision at the request of the employee of accommodation superior to that described in Sub-Regulation (h) above.

4. Medical Attendance

- (i) A patient shall be entitled, free of charge, to medical attendance by the Medical Officer.
- (ii) Where a Patient entitled under sub-regulation (i) free of charge, to receive medical attendance, any amount paid by him/her on account of such medical attendance shall, on production of a certificate in writing by the Medical Officer, be re-imbursed to him by the Port Trust Board.

- (iii) Medical attendance is distinct from Medical treatment and there should be no need for repeated consultations. A maximum of four consultations in a period of ten days of treatment at the consulting room of the Medical Officer or residence of the Patient (other than the Medical Officer of the Port Trust Hospital, where consultation is free of charge) in the case of Allopathic system and twenty days in the case of Indian system of Medicine and Homeopathy is permissible. In cases where the total period of treatment required is not more than 10 days/20 days and no hospitalisation is required but the number of consultations may require more than four, such cases should be referred to the Outpatient department of the Hospital. Beyond this, the patient should be referred for treatment as inpatient in the Port Trust Hospital or one of the approved Hospitals. The rates for the first and subsequent consultations as well as injections other than in the Port Trust Hospital will be reimbursed to the extent periodically determined by the Central Government for its own employees.

5. Travelling Allowance for Medical Attendance Journeys

- (i) When the place at which a patient falls ill is more than eight Kilometers by the shortest route from the Consulting room of the Medical Officer.
 - (a) the patient shall be entitled to travelling allowance for the journey to and from such consulting room.
 - (b) if the patient is too ill to travel, the Medical Officer shall be entitled to Travelling Allowance for the journey to and from the place where the patient is ill.
- (ii) Claims as per sub-regulation (i) above shall be accompanied by a Certificate in writing by the Medical Officer stating that medical attendance was necessary and if the application is under clause (b) of this sub-regulation, that, the patient was too ill to travel.
- (iii) The admissibility of travelling Allowance in these cases will be as follows :
 - (a) For the employees as per actuals limited to mileage allowance at tour rates (without daily allowance) and to members of family actual conveyance charges limited to half the mileage allowance at tour rates (without daily allowance).
 - (b) Reimbursement of Ambulance charges will be regulated as per regulations framed for the hire of the ambulance in the case of Port trust ambulance. In case, ambulances other

than, the Port Trust Ambulance is used the reimbursement is subject to the conditions that :

- (1) It is certified that 'the Medical Officer of the Port Trust Hospital that the Ambulance of the Port Trust is not available.
 - (2) It is certified by the Medical Officer in writing that conveyance of the patient by another means of conveyance would definitely endanger the life of the patient or grossly aggravate the condition of his/her health.
 - (3) The Medical Officer should also indicate in his Certificate whether the ambulance was used to convey the patient to a place of treatment or from one Hospital to another for purposes of certain medical examination.
- (c) An attendant/escort will be entitled to travelling Allowance at the rates admissible under these orders provided it is certified by the Medical Officer that it is unsafe for the patient to travel unattended and that an attendant/escort is necessary to accompany him/her to the place of treatment.

6. A patient shall be entitled free of charge to treatment/attendance in the Port Trust's Hospital/dispensaries.

7. Medical Treatment

- (i) A patient shall be entitled to free inpatient/treatment in the Port Trust Hospital.
- (ii) Where the Medical Officer refers the patient for treatment in an approved Hospital or state Government Hospital either due to absence of facilities in the Port Trust Hospital or the residence of the patient/place where the patient had fallen ill is beyond eight kilometers from the Port Trust Hospital, this should be with the specific permission of the Chief Medical Officer in this regard. Where such permission could not be obtained prior to commencement of the treatment this should be obtained immediately after such admission stating the reasons therefor.
- (iii) In cases referred to sub-regulation (i) and (ii) above any amount paid by the employee on account of such treatment shall, on production of a certificate in writing by the Medical Officer in this regard be reimbursed by the Board. The scale of rates of Kasturba Medical College Hospital, Manipal or of Government Hospital (whichever is higher) for various services including accom-

modation covered under Sub-Regulation (xv) of regulation 3 will be the ceiling limit for such reimbursement.

8. Treatment at Residence

- (i) If the Medical Officer is of opinion that owing to absence or remoteness of a suitable Hospital or to the severity of the illness the patient cannot be given treatment as provided for in regulation 8 above, the patient may receive treatment at his/her residence.
- (ii) A patient receiving treatment at his/her residence under sub-regulation (i) above shall be entitled to receive towards the cost of such treatment incurred by him/her, a sum equivalent of the cost of such treatment as he/she would have been entitled, free of charge, to receive under these regulations if he/she had not been treated at his/her residence.
- (iii) Claim as at sub-regulation (ii) above shall be accompanied by a Certificate from the Chief Medical Officer stating :
 - (a) reasons for his opinion as at (i) above;
 - (b) Cost of similar treatment as referred to in sub-regulation (ii) above.

9. Other Medical Facilities

Reimbursement is admissible for the following kinds of treatment as per these regulations :

- (i) "Venereal Diseases" and "Delirium tremens"
- (ii) Treatment for Sterilisation as a measure of family limitation.
- (iii) Medical termination of pregnancy if performed by Hospitals/Institutions approved by the Central Government.
- (iv) Dental Treatment such as extraction, scaling and gum treatment, filling of teeth, root canal treatment and dental treatment of major kind such as treatment of Jaw bone disease, wholesome removal of teeth if the real source of disturbance for the employee suffering from physiological or other disability is on account of teeth.
- (v) Anti-rabi treatment.
- (vi) Correction of squint (cyc).
- (vii) Purchase/replacement/repair/adjustment of hearing aid on the recommendation of the E.N.T. Specialist and payment will be made direct to the supplying agency subject to ceilings prescribed from time to time by the Central Govt. for their own employees.

- (viii) The wife of an employee is entitled to receive medical attendance and treatment for confinement in the Port Trust hospital/approved hospital/State Govt. hospital. This will include expenses connected with prenatal as well as post natal treatment. The confinement charges at residence will be reimbursed, if the delivery is conducted by the staff of Child Welfare and Maternity Centres maintained by Govt. or local bodies at the scheduled rates of such centres.
- (ix) Reimbursement of expenses incurred by the patient for treatment under Indian and Homopathic systems of medicine will be admissible as prescribed by the Central govt. for their own employees.

10. Procedure for Sanctioning Claims for Reimbursement of Hospital charges :

- (i) Claims for reimbursement of hospital charges covered under these regulations shall be submitted by the employee in the prescribed form (at present the form of application and the essentiality certificate as prescribed for the Central Govt. Servants is prescribed for the Post Trust employees also) to the head of the department within 90 days from the date of completion of treatment. In case the treatment is prolonged and continued, claims may be submitted in stages for a period of not less than 30 days.
- (ii) Delay in submission of claim beyond the prescribed time limit may be condoned by the respective head of the department on merits of each case.
- (iii) The following vouchers and certificates from the hospitals in which the patient has undergone treatment should be submitted by the employee concerned along with the claims in the prescribed form :
 - (a) Hospital Bill with full name of the patient and if a family member name and full particulars of the employee concerned. The details of the various charges should also be given.
 - (b) receipt for payment made if the bill itself is not a receipt.
 - (c) Admission and discharge certificate.
 - (d) cash memos for purchase of medicines (need not be stamped or bear the supplier's acknowledgement) shall be countersigned by the Medical Officer of the hospital incharge of the patient.
 - (e) For reference to an approved hospital the certificate of the medical officer of the Port

- Trust Hospital who referred the patient to the hospital.
- (iv) The claims of the employees shall be scrutinised by the respective Heads of Departments and the sanction of the Chairman obtained wherever necessary and the claim forwarded after counter-signature to the Financial and Chief Accounts Officers for payment. In the case of reimbursement of the claim other than attendance/treatment in the Port Trust/approved/State Govt. Hospitals and requiring the certificate of the Chief Medical Officer and/or sanction of the chairman, the claim shall be scrutinised by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer before sanction by the chairman in relaxation of these Regulations.
- (v) A sub-register shall be maintained in each Department to continuously detail the claim reimbursed, in a chronological order to enable periodical review to prevent abuse of medical reimbursement facilities.
- (vi) A patient treated under allopathic system may purchase medicines from all Chemists and Drugists licenced under the Drugs and Cosmetics Act and rules thereunder. In the case of Patient treated under Ayurvedic, Unani, Siddha and Homopathic system, the medicines shall be purchased only from authorised dealers as per list indicated in Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

11. Procedure for Payment to Approved Hospitals

In all cases where the employees are referred for treatment in the Hospitals approved by the Board under Regulation 3(ii) the payment for the charges payable by the employees will be directly made to those Hospitals by the Port Trust. If, on submission of the final claim it is found that the payment is in excess of the amount admissible, the excess will be recovered from the pay drawn by the employee immediately thereafter in monthly instalments not exceeding four. The Chairman may increase the number of instalments examining the cases on their merits.

12. Interpretation

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Board.

13. Power to Relax

The Power to relax any of the provisions of these regulations shall rest with the Board.

14. Repeal and Saving

On the commencement of these regulations, every rule, regulation, resolution or order in force immediately before

such commencement, shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these regulations cease to operate.

APPENDIX—I

SANCTIONING AUTHORITY FOR THE PURPOSE OF REIMBURSEMENT OF HOSPITAL CHARGES (Vide Regulation 3)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1. Claim relating to reimbursement of Hospital charges in respect of Heads of Departments

2. Relaxation as per Regulation 10 (iii)

3. Class I to IV employees excluding Head of Heads of Depts. | } | Chariman

Dy. Chariman/
Heads of
Depts. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|

APPENDIX—II APPROVED HOSPITALS (Vide Regulation 3 (ii))

1. Father Mullers Hospital, Kankanady, Mangalore (Item No. 8 of Meeting No. 3 of 1983-84).
2. Kasturba Medical College Hospital, Manipal at Uniform Concessional rate of 10% less than the nominal hospital charges (item 15 of Meeting 9 of 1986-87).
3. Dr. Tonse Madhava Anantha Pai Rotary Hospital, Bejai, Mangalore (item 19 of Meeting No. 6 of 1989-90)
4. Unity Health Complex, Kankanadi, Mangalore at 30% concessional rates less than the normal hospital charges (item No. 21 of Meeting No. 6 of 1989-90)
5. St. Martha's Hospital, Bangalore for the treatment of employees of New Mangalore Port Trust at Trade Promotion Centre, Bangalore. An amount of Rs. 5000/- has been deposited with the Hospital as security deposit by the New Mangalore Port Trust (item No. 10 of 3rd Board Meeting of 1990-91).
6. Extension/ Branches of Kasturba Medical College Hospital, Manipal Group in Dakshina Kannada District.

REFERENCES AND NOTES

REGULATION 2

Sub Regulation (i) and (iv) adopted from Madras Port Trust Regulation.

- do- (ii) (iii) adopted from C.S.M.A.Rules.
- do- (v), (vi) and (viii) as applicable in Madras Port Trust and N.M.P.T.
- do- (vii) adopted from Mormugoa.

REGULATION 3

Sub Regulation (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xv) adopted from Madras Port Trust.

- do- (vii) and (xv) from Madras Port Trust and

CS. M.A. Rules.

Sub Regulation (x) and (xii) from Mormugoa.

REGULATION 4

From Mormugoa. and C.S. M.A. Rules.

REGULATION 5

Sub Regulation (i) to (iii) C.S. M.A. Rules.

-do- (iv) —item 7 of Board Meeting of 1992-93 (30-1-1993)

REGULATION 6

Adopted from Madras, Marmugoa.

REGULATION 7, 8, 9, 10.11—

Adopted from C.S. M.A. Rules.

REGULATION 12 and 13

Adopted from Mormugoa, J.N. P.T., Calcutta.

REGULATION 14

Adopted from Calcutta.

NCTES

(i) The regulations have been framed taking into account the existing procedures in the N.M.P.T. and based on C.S.M.A. Rules suitably modified to suit Port Trust conditions drawing on the regulations of other Port Trusts.

(ii) K.M.C. Hospital, Manipal is recognised by the Central Government with which arrangements have been made by the Government for the treatment of Central Government servants under Rules 2(d) of C.S.M.A., Rules and as such full reimbursement has been allowed (The Hospital also allows 10% concession rates). The Madras Port Trust allows the same terms for the hospitals approved by the Board for the Port Trust employees. In the case of Hospitals approved for treatment by the Port Trust Board as detailed in Appendix II to these Regulations their status is the same as K.M.C. Hospital, Manipal in respect of Central Government employees and the approved Hospitals of Madras Port Trust. As such full reimbursement of Hospital charges are proposed subject to the upper limit of K.M.C. rates already approved by the Govt.

(iii) In the case of Retired employees and hire for use of Ambulance charges the separate regulations are retained.

(iv) List of admissible medicines on Allopathic system and admissible medicines for Indian system and homeopathy are adopted from C.S.M.A. Rules.

(v) Form of application and essentiality Certificate adopted from C.S.M.A. Rules.

(vi) Provision for direct payment to Hospitals as available in C.S.M.A. Rules for reference to Private Hospitals adopted for the Private Hospitals approved for treatment.

[F.N. 12016/26/95-PET]
K. V. RAO, Jt. Secy.

